

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1999 को धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 किसे कृषि अधिनियम कक्षा तथा धारा 4 में-

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

“(क) सरकार का प्रमुख सचिव/ सचिव, पशुपालन विभाग, पदेन सदस्य”

(ख) उपधारा (2) में शब्द “उपाध्यक्ष” के स्थान पर शब्द “अध्यक्ष और उपाध्यक्ष” रख दिये जायेंगे।

निरसन और अध्यादेश

3-(1) उत्तर प्रदेश गौ-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2013 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2013

(2) ऐसे निरसन के होने, हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सार्वजनिक समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

गाय और गाय के रक्षण और कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश में गौ-सेवा आयोग की स्थापना करने के लिये उत्तर प्रदेश गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1999) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 4 में उक्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गयी है। उक्त धारा के मूलतः यह व्यवस्था की गयी थी कि सरकार का सचिव, पशुपालन विभाग, आयोग का पदेन सदस्य होगा और आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सरकार द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों में से नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश गौ-सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 2007) द्वारा उक्त धारा में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी गयी थी कि सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग, आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा और आयोग का उपाध्यक्ष सरकार द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों में से नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे। उक्त आयोग का कुशलतापूर्वक कार्य संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त धारा को संशोधित करके यथोक्त पहले की पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाये।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था। अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 जून, 2013 को उत्तर प्रदेश गौ-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2013) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये प्रस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस0के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No 1038(2)/LXXIX-V-1-13-1(3a)11-2013

Dated Lucknow, September 26, 2013

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 24, 2013.

THE UTTAR PRADESH GO SEVA AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013
(U.P. ACT NO. 17 OF 2013) [

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Go Seva Ayog Adhiniyam, 1999.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on June 6, 2013.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Go Seva Ayog Adhiniyam, 1999 hereinafter referred to as the principal Act, — Amendment of section 4 of U.P. Act no. 15 of 1999

(a) in sub-section (1) for clause (a) the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) Principal Secretary/Secretary to the Government in the Animal Husbandry Department Ex-officio Member”

(b) In sub-section (2) for the word “Vice-Chairperson” the words “Chairperson and the Vice-Chairperson” shall be substituted.

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 2013 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 7 of 2013

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Go Seva Ayog Adhiniyam, 1999 (U.P. Act no. 15 of 1999) has been enacted to provide for the establishment of a Go Seva Ayog in Uttar Pradesh for the preservation and welfare of the cow and its progeny. Section 4 of the said Act provides for the constitution of the said Ayog. Originally the said section provided that the Secretary to the Government in the Animal Husbandry Department shall be the *ex-officio* member of the Ayog and the Chairperson and the Vice-chairperson of the Ayog shall be nominated by the State Government from amongst the non-official members. By the Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (U.P. Act no. 9 of 2007) the said section was amended to provide that the Principal Secretary/Secretary, Animal Husbandry Department shall be the *ex-officio*

के उपरोक्त सूचना -
देश संख्या-377
आ-4/जी-2-

02/2024-25
का सर्वप्रथम प्रकाश
के सम्बन्ध में।

क्रम संख्या-162

Chairperson and the Vice-chairperson of the Ayog shall be nominated by the State Government from amongst the non-official members. With view to ensuring the efficient working of the said Ayog it was decided to amend the said section to enforce the old provisions as stated above formerly.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Samudhan) Ordinance, 2013 (U.P. Ordinance no. 7 of 2013) was promulgated by the Governor on June 6, 2013.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.K. PANDEY,
Pranukh Sachiv

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 447 राजपत्र(डि०)-2013-
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 78 सा० वि०